RAJA SABHA

Friday, the 4th May, 1979/the 14th Vaisakha, 1901 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: I have to refer with profound sorrow to the passing away of Shri Shankar Pratap Singh, an ex-Member of this House.

Born at Chichili in District Narsinghpur of Madhya Pradesh in 1922, Shri Shankar Pratap Singh was educated at Nagpur University. He was an agriculturist and social worker. He was a Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 1952 to 1957. During his tenure of membership of the Rajya Sabha from 1966 to 1972, Shri Shankar Pratap Singh evinced keen interest in the proceedings of the House.

We deeply mourn the passing away of Shri Shankar Pratap Singh.

I would request Members to rise in their places and observe a minute's silence as a mark of respect to the memory of the deceased.

(*Hon. Members then stood in silence for one minute*).

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the breaved family our sense of profound sorrow and sympathy on the passing away of Shri Shankar Pratap Singh.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रेट अंदमान रोड का निर्माण

*141. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान द्वीप समूह में ग्रेट अन्दमान रोड का 90 मील का हिस्सा बन कर तैयार हो चुका है लेकिन इसका 15 मील का हिस्सा अभी पूरा करना बाकी है ; और

(ख) यदि हां, तो सड़क के उक्त हिस्से के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

†[Construction of Great Andaman Road

*141. SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 90 mile stretch of Great Andaman road in Andaman Islands has been completed but a 15 mile stretch is yet to be completed; and

(b) if so, what are the reasons for the delay in completing this part of the road and by when this is likely to be completed?]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय दक्षिणी अंदमान में ग्रेट अंदमान ट्रक रोड के निर्माण से है । दक्षिणी अंदमान में इसकी लम्बाई 110 किलोमीटर है जिसमें से 87 किलोमीटर तक निर्माण का काम पूरा हो चुका है । स्थानीय प्रशासन के आदेश पर प्रशासनिक कारणों से इस पर आगे निर्माण कार्य सितम्बर, 1975 में स्थगित कर दिया गया था । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

---

†[ ] English translation.

†[THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b) Presumably, the Member is referring to the Construction of G.A.T. Road in South Andamans. Of its total length of 110 Kms. in South Andamans, 87 Kms. have already been completed. Further work was suspended in September, 1975 at the instance of the Local Administration for administrative reasons. It is not possible at this stage to indicate any date of completion.]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमान, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने इस जवाब की ओर ध्यान दिया । इस तरह का स्टिरियो टाइप जवाब कोई पटवारी भी नहीं देता । मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि इस कार्य को स्थानीय प्रशासन ने रोक दिया है । क्यों रोका गया इसका कारण नहीं बताया और आज भी कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझते । जब कोई सड़क बनती है तो उस सड़क का नक्शा बनता है, एस्टीमेट बनता है जो कि सेंक्शन होता है और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है । यह सारा काम स्थानीय प्रशासन के आदेश से ही होता है । जब सड़क का नक्शा बना, एस्टीमेट बना और वह सेंक्शन हुआ तो उस समय आपके प्रशासन ने इस काम को नहीं रोका । साउथ अंदमान में यह जो सड़क है वह पूरी बन गई है परन्तु बीच मे 15 मील के करीब सड़क बनने से रोक दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सा कन्ट्री के डिफेन्स का सवाल इनवाल्व है । केवल कन्ट्री के डिफेन्स और सिक्योरिटी का ही ऐसा मसला हो सकता है जिसमें मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मैं बतला नहीं सकता और कोई कारण ऐसा कहने का नहीं हो सकता । इस सड़क का बनना क्यों रोक दिया गया इसको मंत्री जी नहीं बताना चाहते । परन्तु मैं बताना चाहता हूं श्रीमन्, कि इंजीनियर चाहते हैं कि यह प्रोजक्ट कभी कम्प्लीट न हो । वह चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो there should be a continuing process. उसमें उनको लाभ यह होता है कि दो करोड़ की प्रोजेक्ट अल्टीमेटली पांच करोड़ का हो जाता है और यह देश में सभी को मालूम है कि इसका आधा हिस्सा तो इंजीनियर्स और ठेकेदारों की पाकेट में जाता है । इसलिए चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट कम्पलीट न हो, 10 साल तक चलता रहे और कारण यह वे बताते हैं चूंकि यह आदिवासी एरिया है, यहां पर आदिवासी बसते है, आदिवासी सड़क बनाने से डिस्टर्ब हो जाएंगे । इसलिए यह सड़क बनाने का काम रोक दिया गया है । मैं मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि शुरू शुरू में जब यह सड़क स्वीकृत हुई बननी शुरू हुई, तब भी यह आदिवासी क्षेत्रों से पास कर रही थी, उस समय क्या यह ख्याल नहीं किया गया कि उस सड़क के बनने से आदिवासी डिस्टर्ब होंगे ? यदि ख्याल नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? दूसरी बात यह कि क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि आदिवासी लोगों को और सम्पर्क में ला कर के उन्हें सभ्य बनाया जाए, एजूकेट किया जाए, उनको माडर्न लाइफ में लाया जाए, हर तरह से उनको डेवलप किया जाए । मैं यह कहना चाहता हूं कि डेवलप करने का पहला प्रासेस रोड होता है कि वहां तक रोड़ चली जाए । इन दो कारणों से क्या यह आवश्यक नही है कि उस सड़क को कम्पलीट कर दिया जाए और मंत्री जी क्या यह भी बतायेंगे कि दोनों ओर से सड़क बना दी गई है और बीच में 15 मील की सड़क छोड़ दी गई है, क्या इस 15 मील को छोड़ने से इस सड़क की पूरी उपयोगिता समाप्त नहीं हो जाती है ?

†[ ] English translation.

श्री चांद राम : यह तो मेरा काम उन्होंने आसान कर दिया है। उन्होंने खुद ही सवाल किया है और खुद ही उसका जवाब दे दिया है। मैंने तो इसमें कहा था कि प्रशासनिक कारणों की वजह से वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया है। मैंने यह नहीं कहा, मैंने कारण नही बताएं, इतना ही कहा कि प्रशासनिक कारण हैं उनको मैं कैसे बता दू। यह बताना पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं है।

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: This is not a security issue.

श्री चांद राम : अब मैं यह पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं बताना चाहता हूं। आप मुझे कैसे . . .

(Interruptions)

श्री सदाशिव बागतकर : प्रशासनिक कारण का क्या मतलब होता है।

श्री चांद राम : उन्होंने खुद कहा कि ट्राइबल वगैरह है। पता नहीं कहां से ले आए। मैंने तो जवाब में ऐसा नहीं कहा। उन्होंने खुद कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के कारण हुआ। अब उनसे पूछें कि वे कहां से यह इत्तला ले आए हैं। जवाब में मैंने कहा . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं प्रश्न कर रहा हूं। जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है।

श्री चांद राम : आपकी भी जिम्मेदारी है। यह कहना कि पटवारी की तरह से जवाब दे दिया, आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं तो आप यह भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं। अगर आपकी यह जिम्मेदारी की बात है तो . . .

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : स्टीरियो टाइप जवाब नहीं होना चाहिए . . .

(Interruptions)

श्री चांद राम : मैं कोई आज का मिनिस्टर नहीं हूं। पब्लिक इंट्रेस्ट मे हम आपको रोक सकते हैं। जब कोई चीज़ बताना पब्लिक इंट्रेस्ट में न हो चेयरमैन साहब आप ही बताइये कि यह अपने अधिकार में है या नहीं है कि पब्लिक इंट्रेस्ट में कोई इत्तला रोकी जा सकती है। हां, अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं प्राइवेट में उनको बता दूंगा लेकिन मैं यहां पर बताने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि इसमें पब्लिक इंट्रेस्ट इनवाल्व है। प्रशासनिक कारणों से मैंने कहा। मैं उनसे अदब से कहूंगा कि अगर मेरे पास वे आएंगे तो मैं उनकी संतुष्टी कर दूंगा। . . . *(Interruptions)* यह जो टोटल लैंथ सड़क की थी वह 343 किलोमीटर थी। इसमें चौथी प्लान के अन्दर 216 किलोमीटर पूरी हो गई तथा 6 किलोमीटर पर काम चल रहा है। 15 किलोमीटर का हिस्सा क्यों नहीं बन सका, इसके लिए मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, जो मैंने दो बातें कहीं, अगर मंत्री जी को मेरे शब्दों से दुःख था तो मैं उनको वापस लेता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपके अधिकारियों ने इस सड़क को बनाने के लिए सोचा, उन्होंने नक्शा बनाया, एस्टीमेट बनाया और वह सैंक्शन हुआ तब क्या उन्होंने नहीं सोचा कि यह सड़क आदिवासी एरिया से पास करेगी। आप और आपके अधिकारी पब्लिक मनी के साथ जोक करते हैं और आप यह महसूस करते हैं, हम लोगों के शब्दों को फील करते हैं। आपने दोनों रोड बना दिये परन्तु बीच में पैच छोड़ दिया इसलिए इस पूरे रोड का कोई महत्व नहीं रहा। आप आप कहते हैं कि प्रशासनिक कारणों से रोक दिया। वे क्या कारण है? आपका प्रशासन बिल्कुल नालायक है . . .

(Interruptions)

श्री चांद राम : चेयरमैन साहब, मेरी मिनिस्ट्री इसमें डाइरेक्टली इन्वालव नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री का काम तो टैक्निकल एडवाइज देना और ओवरसी करना है। ये दो काम हमारी मिनिस्ट्री करती है। परन्तु यह चूंकि यूनियन टेरीटरी है इसलिए . . .

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: As Government, you will have to satisfy hon. Members.

श्री चांद राम : लेकिन चूंकि यह यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का है इसलिए उनको काम करना है। वह काम चल रहा है और सी० पी० डब्ल्यू० डी० के मारफत वहां काम चल रहा है एक्जीक्यूट हो रहा है। इन्होंने यह रिपोर्ट की कि 15 किलोमीटर के हिस्से में वह सड़क नहीं बन सकती है। फिर मैं जब अन्दमान गया तो वहां के चीफ कमिश्नर से बात की कि इस सड़क को जल्दी कम्प्लीट कराइये। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कारणों से सड़क को नहीं बना सकते हैं। हम मुकामिल लोगों को समझा रहे हैं जब वे समझ जायेंगे तब उस वक्त हम उस सड़क को बनायेंगे।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री चांद राम : आप गुस्से में क्यों हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : नहीं मैं गुस्से में नहीं हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। इसमें पब्लिक मनी इन्वाल्वड है। आपने कहा कि हमारे महकमे से इसका ताल्लुक नहीं है। यह यूनियन टेरीटरी है। रुपया दिल्ली सरकार का है, सी० पी० डब्ल्यू० डी० दिल्ली की सरकार का है तो अब मैं क्या विदेश मंत्री से पूछुंगा ?

श्री चांद राम : श्रीमन्, मैंने यह कहा कि मैंने चीफ कमिश्नर से कहा कि इसको जल्दी कराया जाय। जहां तक फण्ड देने का सवाल है गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फण्ड दे दिये हैं। फण्ड देने के लिए तैयार हैं, फण्ड की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बनाने की है। वह नहीं बना सकता है इसलिये मैंने उनको यह बताया।

PROF. N. G. RANGA: May I know, Sir, how much of this road is now in use and when will it open to traffic? Why is it that Government have not thought of diverting the route or the alignment? Is it that some private property or some religious property or something like that has come in the way because of which they are not able to acquire it? How soon do they expect to complete the road except that particular portion and in regard to that portion also, would Government consider realignment of their plan so that they can complete it as soon as possible? I was also there in the Andamans. I know how important it is for them to have this road and that place is suffering for want of communication. My hon. friend should not be satisfied by saying that they are only advisers. They are advisers as well as administrators on behalf of the Government of India. Every department of the Government of India is not functioning there in connection with the local administration and the local administration is not a self-governing administration but is very much dependent on this Government.

SHRI CHAND RAM: I have only indicated the position so far as the functioning of my Ministry *vis-a-vis* the Andaman administration is concerned. I have only indicated that position. I have not said that we are not keen that this road should be completed. We have provided funds. We are giving them technical and

overseeing guidance and that guidance is available to them. We have also impressed upon the Administration that this road should be completed. But any road in an area can be completed only with the co-operation of the people, the local people, for whom this road is being constructed. If they are opposing, they have to be persuaded first. I think, you will agree with me in this in view of the position obtainable there.

SHRI V. C. KESAVA RAO: Sir, in the Andamans, there are more than 300 islands. This Great Andaman Road goes only in the Andaman is land. There are other inlands also. But there are no roads in the other islands. May I know whether the Government is contemplating to construct any roads in the other islands where there is some population and where we have some refugees from Bangladesh?

SHRI CHAND RAM: If any proposal comes up, we will consider it.

SHRI V. C. KESAVA RAO: I wanted to know whether the Government is thinking of constructing roads in all the other Islands connected with the Andaman Islands?

SHRI V. GOPALSAMY: About one lakh and fifty thousand people are living in the Andaman. Fifty percent of them are from the South Indian States. The Andaman Island was used by the British people to imprison the freedom fighters of India, but the same atmosphere is being continued there even after 30 years of independence. It is not only the question of constructing the Great Andaman road in Andaman Islands, even other facilities of transport and communications have not been provided to the people of the Andamans. Also the Minister is evading the question of Mr. Shahi because he says that he is prepared to reply to him privately and not on the floor of the House. I would like the Minister to inform the House about the administrative reasons why the road facilities have not been provided so far. The reasons should be given on the floor of the House. The Government should undertake a time-bound programme to provide better facilities, better road and transport facilities there. I want to know from the Minister whether he is prepared to say in the House that he will undertake a time-bound programme for providing the facilities in the Andamans.

SHRI CHAND RAM: It is not correct to say that we are not paying enough attention to the development of the Andamans. I have been to Andaman recently. I have called a meeting here last month only where the Chief Commissioner of the territory and other administrative officers were called. I addressed a meeting of the administrative officers there and I have told them that there is no paucity of funds. This scheme should be prepared and put up. If any hon. Member takes the trouble of going there . . .

SHRI G. LAKSHMANAN: We have had the experience of our Member going there and dying there.

SHRI CHAND RAM: If a natural death takes place . . .

SHRI G. LAKSHMANAN: There was no officer, no facility.

(Interruptions)

SHRI CHAND RAM: Sir, I can only say tat during te last two years we have formulated many schemes. We are executing many schemes and we are seeing that these Islands make progress. Enough funds have been provided for tem.

श्री भोला पासवान शास्त्री : क्या सरकार . . .

श्री शिव नारायण : जब सवाल नहीं सुनेंगे, तो जवाब क्या देंगे ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रोड बनानी बन्द कर दी गई है, वह इसलिए बन्द कर दी गई है कि जो बाहर के मेनलैण्ड से रिफ्यूजीज वहां बसाए गए हैं और जो बस रहे हैं उस रोड में से जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, जंगल की बर्बादी होती है और जो वहां का स्पेशल ट्राइब मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब झरवा है, उससे सम्पर्क होता है और उसको इक्सप्लाइट करते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि रोड जल्दी बने और वहां यह लोग जाएं, जंगल को आबाद करें, भूमि को बनायें, अपनी सम्पत्ति बढ़ावें, जिसका नतीजा होता है कि झरवा ट्राइब बर्बाद हो रहा है क्योंकि उसका जो रहन-सहन बरसों से है, वह बाहर के लोगों से मिलने से उनमें तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती है और वह वंश खत्म हो रहा है। उसको बचाना सरकार और हम सबके लिए बहुत जरूरी है और वह तभी हो सकता है जब उन्हें जंगल में रहने दिया जाये। वह जंगल रिजर्व कर दिया गया है ताकि उसमें कोई जा नहीं सके। लेकिन यह लोग कहते हैं रोड बने क्योंकि वहां जाने का एक ही रास्ता है, एक तो समुद्र के रास्ते से वहां जाना इन लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन जहां रिफ्यूजी बसाए गये हैं, यह काफी अच्छा काम किया गया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि उनको छूट दी जाये कि जो वहां की प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनके वहां रहने से वे बर्बाद हो जायें उनको रोकने के लिए वे मोटर लेंगे, सवारी लेंगे, वहां पहुंचेंगे। उनको एक्सप्लाइट करते हैं। लकड़ी काटने से ही उनको सरोकार होता है। वे अभी भी इस अवस्था में हैं कि तीर लेकर निकलते हैं ला एण्ड आर्डर का सवाल होता है, यह बात है कि नहीं? इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये क्या गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाया गया है?

श्री चांद राम : मैं आदरणीय सदस्य शास्त्री जी को इस सूचना के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री नत्थी सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है . . .

(*Interruptions*)

श्री भोला पासवान शास्त्री : क्या जवाब दिया मंत्री जी ने, सुना नहीं?

श्री चांद राम : इस सूचना के लिए मैंने आपको धन्यवाद किया।

श्री नत्थी सिंह : क्या यह सही है कि अंडमान निकोबार में परिवहन की समस्या अत्यन्त ही कठिन है, जिससे वहां के किसानों की पैदावार बिकने नहीं जा सकती, समुद्र में उसे फेंकना पड़ता है, दूसरी जगह सब्जी तक मिलती नहीं है। इसलिए इस परिवहन को समस्या को सुलझाने के लिए इस सड़का का पूरा बनना बहुत आवश्यक है। और क्या यह सही है कि यह 15 किलोमीटर का जो टुकड़ा है उस भूभाग में हो कर जाता है जहां कि झारवा ट्राइब के लोगों से अंडमान निकोबार प्रशासन का सम्पर्क नहीं हो पाया है। यह 15 किलोमीटर का सम्पर्क कहा हुआ है जिससे यह दिक्कत आ रही है।

श्री चांद राम : चेयरमैन साहब, यह ठीक है कि परिवहन की ट्रांसपोर्ट की समस्या वहां कठिन है इसलिए यातायात के साधनों की भी कोशिश कर रहे हैं और जहां भी हो सके, ज्यादा फण्ड दिए जाएं और उसकी सहूलियत को बढ़ा कर दिक्कत को आसान किया जाय और हमने आगे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि अगर यातायात की, ट्रांसपोर्ट की, खास तौर पर तकलीफ है, तो उसके लिए और फण्ड देने के लिए तैयार हैं। इनमें तो

हमने सबके कोआपरेशन से मिल कर काम करना है।

D.T.C. bus service to resettlement colonies

*142. SHRI M. R. KRISHNA:
SHRI JAGJIT SINGH ANAND:†
SHRI LADLI MOHAN NIGAM:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the names of the resettlement colonies established since 1976 which do not have direct bus service to Central Secretariat/Connaught Place/ Delhi Main Railway Station and Inter State Bus Terminal; and

(b) what steps Government propose to take to start bus service on new routes for ensuring direct connections to the above mentioned places from these colonies?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) All the resettlement colonies established since 1976 are connected by DTC bus service to either Central Sectt. or Connaught Place or Delhi Main Railway Station or I.S.B.T.

(b) It is not feasible to provide direct services from the resettlement colonies to all the four abovementioned places. However, convenient change over facilities are available for travelling from the resettlement colonies to all the abovementioned places.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, firstly I had asked specifically the names of the resettlement colonies established since 1976 which did not have direct bus service to all these places. It would have been better if the hon. Minister had supplied the names and indicated that this colony is connected to this place and this is connected to this place and said that it is not possible to connect all these colonies to all those four places. Without that the supplementaries could not come up.

Sir, I have definite information regarding one colony—Shakarpur—which is not directly connected to any of those places. I mentioned four places. This is my information. The Minister's information may be different. I want to ask the Minister if he is aware that these resettlement colonies came up under a very tragic situation when right in the midst of the monsoon, soon after the declaration of the emergency, the *jhugis* of the poorest of the poor were demolished, they were uprooted and sent there during the rainy season, and they spent the whole of next winter under the sky. Upto now, there is no sewerage in these colonies; most of them do not have electricity; most of them do not have the basic amenities. And even on the question of transport, it is important to remember that some of them were taken from old Subzi Mandi to places about 20 kilometres off and even with the transport charges then prevailing—because there was no direct connection—they could not earn as much as they would have to spend on transport coming from that place to their place of work. Now recently the transport charges have also gone up.

In view of this, will the hon. Minister give two assurances. One, that these colonies will be connected to these four places. This is necessary because one or the other will be close to the place of their work from where they can walk further distances. And two, that at least in the

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagjit Singh Anand.